बाणिज्यिक कर विभाग
मंज़ालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जानवरी, 2015

क्र. एक बी-4-29-2014-2-पाँच(01).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक साक्ष्यों को प्रभावित में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अंतिमित करते हुए, राज्य सरकार, एकत्र विभाग, उत्तर अधिनियम की अनुसूची 1-क के कॉलम (2) में उल्लिखित अनुच्छेदों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क कम करती है/चूक प्रदान करती है, अर्थात्—
<table>
<thead>
<tr>
<th>अनुक्रमांक</th>
<th>अनुक्रेणद</th>
<th>कमी/घुट</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>अनुक्रेणद -5— शाखा बाट</td>
<td>1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी संसदव्य द्वारा ग्रेहत प्रतिज्ञात किये गये शाखा-पत्र पर।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>करार या करार का झापन</td>
<td>2. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिनियम का कार्य के अनुसार 8—25—4—84, दिनांक 28 दिसम्बर,1984 में राज्यसभानिर्देश अन्य निर्देश वर्ग के किसी संसद द्वारा प्रतिज्ञात किए गए शाखा-पत्र पर।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग के सम्बन्ध में प्रस्तुत शाखा-पत्र पर।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4. भीपाल गैस विभागिता (थांबा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 (1985 का 21 ) के अधीन प्रस्तुत शाखा-पत्र पर।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5. रोग अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौ सेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) या बायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अधीन गठित होने के लिए प्रस्तुत शाखा पत्र पर।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6. किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय के अधिकारियों के सम्बन्ध में फाइल फिरता जाने वा उपयोग में लाए जाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए प्रस्तुत शाखा पत्र पर।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>7. किसी व्यक्ति को कोई योजना या पुष्पद्र क्षत्र प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए प्रस्तुत शाखा पत्र पर।</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>अनुक्रेणद—6— करार या करार का झापन</td>
<td>1. मध्यप्रदेश खादी तथा प्रामोदोंग बोर्ड के अधीन इकाइयाँ द्वारा बोर्ड से सहायता प्राप्त करने के लिये निर्देशित लिखित पर।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. गरीबी रेखा के नीचे जीवन-धारण करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रति उपयोगिता द्वारा मेधार युक्त एक-एक वर्ती विशेष कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश विशेष वितरण कम्पनी जबलपुर, भीपाल तथा इंडोर के साथ निर्देशित किए जाने के लिए अपेक्षित करार की लिखित पर।</td>
</tr>
<tr>
<td>अनुक्रमांक</td>
<td>अनुच्छेद</td>
<td>कमी/छूट</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>1. विस्तार केंद्र कार्ड योजना की अर्थगत ऋण को प्रतिमूल करने के लिए क्रेडिट द्वारा बैंकों के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली लिखितों पर।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>2. नबाब्द आधारवर्तित स्थिरों के अधीन समूह के सदस्यों के आर्थिक विकास हेतु दस लाख रुपये तक के ऋण को प्रतिमूल करने के लिए स्व-सहायता समूहों द्वारा बैंकों के पक्ष में निष्पादित किए जाने वाली लिखितों पर।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>3. औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अभिप्राप्त किए गए ऋणों का प्रतिमूल दुनिया अनुसार करने के लिए किसी वित्तीय संस्था के पक्ष में जदी बूटी या आयुक्तवर्त के हेतु अभावण उद्योगों द्वारा निष्पादित लिखितों पर नियमित प्रति अनुवंधन सर्वराज्य नीति, 2010, यह सर्वसम्मिलन 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग सर्वराज्य नीति, 2014 तथा उसकी कार्यान्वयन से प्रवर्तन में रहने तक एक स्टाम्प शुल्क के से छूट होगी।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(क) औद्योगिक इकाइयां मध्यप्रदेश सरकार या मध्यप्रदेश औद्योगिक केंद्र विकसित निमाता द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक केंद्र या औद्योगिक कूट (सोडु) केंद्र में पश्चात हो, तथा</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(ख) आयुक्तवर्त के हेतु आयुक्तवर्त मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस आशय का एक पारित आयुक्तवर्त जारी किया गया हो कि यह उद्योग इस आशय के अधीन स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए पात्र है।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>4. मध्यप्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन परियोजनाओं के लिए निष्पादित की जाने वाली राजस्थानी भूमि के विकास अनुवंध की लिखितों पर।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>5. शिक्षा ऋण के पुनरुपयोगी से संस्कृति करार की लिखितों पर प्रमार्थ स्टाम्प शुल्क की दर को घटाकर केंद्र पार्च सी सूपर किया जाता है।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>6. तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को स्थापना के लिए बैंक के साथ निष्पादित किये जाने वाले ऋण संबंधी लिखितों पर स्टाम्प शुल्क घटाकर केंद्र पार्च सी सूपर किया जाता है।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>7. करार या करार का आयाम -</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(क) जो अनुस्थान माल के वाणिज्य के विक्रम के लिए है या उससे संबंधित है और जो अनुक्रम 46 के अधीन प्रमार्थ नौट या आयाम नहीं है।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(ख) जो केंद्रीय सरकार का किसी ऐसी विनियमों के रूप में किए गए हैं, जो किसी उद्देश्य के लिए हैं या उससे संबंधित हैं।</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| 3.        | 8. मध्यप्रदेश राज्य के प्रामाण्य बोर्ड के अधीन की इकाइयां द्वारा बोर्ड से सहायता प्राप्त करने के लिए निष्पादित की जाने वाली लिखितों पर। |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>अनुक्रमक</th>
<th>अनुच्छेद</th>
<th>कमी/घट</th>
<th>या आदानमार्ग से संबंधित कार्य--</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.</td>
<td>उदाहरण के तहत यदि आयोग एवं महाराष्ट्र विभाग से आयोगिक प्रयोजनों के लिए ऋणों तथा अनुमोदन करने के संबंध में राज्य के उयोगपत्रियों या आयोगिक उपकरणों द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले हक विलेख के निश्चय से संबंधित करनी पर।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>किसान को दित कार्योपयोग के अंतर्गत ऋण प्रतिस्थापन करने के लिए क्रिया के संबंध में हक से विचार किए जाने वाली लिखातों पर।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>नवायोग इकाई में किसानों के अधीन 10 लाख रुपए की सीमा तक निष्कर्ष--सदस्यों के आधिकारिक विकास हेतु ऋण का प्रतिस्थापन करने के लिए स्व-सहायता समूहों द्वारा बैंकों के लिए निर्दिष्ट किए जाने वाली लिखातों पर।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>किसी भूमिगरीण या रेजेंसी बूक पर लैंडप्लाइरी द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए दस लाख रुपए तक के ऋण का प्रतिस्थापन करने के लिए बैंकों के लिए निर्दिष्ट किए जाने वाले हक विलेख के निश्चय पर राज्य, यह भी कि अनुमोदन दिया जाने तथा अनुमोदन जनावाते के सारांश के मामले में उपयोग में रहने वाले मुद्दों को किसी भी सीमा तक कोई स्टॉप शुल्क देने का अस्वीकार होगा।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>आयोगिक प्रयोजनों के लिए अनुष्ठापित किए गए ऋणों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने के लिए उदाहरण के तहत आयोग बूकों में कृषि वित्तीय विभाग द्वारा निर्दिष्ट किए गए अधिकारिक मुद्दों (प्रथम) केंद्र में विचार है, तथा:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(क)</td>
<td>आयोगिक इकाई, महाराष्ट्र विभाग या महाराष्ट्र आयोगिक एवं विकास विभाग निर्माण द्वारा निर्माण किए गए आयोगिक क्षेत्र या आयोगिक बूक (प्रथम) केंद्र में विचार है, तथा:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(व)</td>
<td>सबसे अधिक, उदय, महाराष्ट्र शासन द्वारा इस आयोग का एक पात्र ब्रिक्स प्राधिकूल द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि, यह उदय, महाराष्ट्र आयोग के अधीन स्टॉप शुल्क में घट के लिए पात्र है।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>सुनेन्द्र प्रीडाधिकारी निवेदन क्षेत्र में बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए सुनेन्द्र प्रीडाधिकारी कपिल की किसी नई इकाई /वित्तपत्र इकाई /आधूनिकों का इकाई द्वारा निर्दिष्ट किए गए सामान्यतः केंद्र (एक विलेख का क्षेत्र) / आदानमार्ग की विचारों पर जरूर एक शर्त स्टॉप शुल्क से घट इस एक अनुमोदन देने का अनुमोदन रहेगा कि नई इकाई /वित्तपत्र इकाई /आधूनिकों का इकाई द्वारा सुनेन्द्र प्रीडाधिकारी निवेदन नीति, 2012 यथासंरचना 2014 अधिन महाराष्ट्र निवेश प्रबंधन केंद्र आउटसोर्सिंग / निवेश संस्थाओं प्रबंधन (सीईओ की समीक्षा) उदय, महाराष्ट्र निवेदन नीति, 2014 के अधीन सुनेन्द्र प्रीडाधिकारी निवेदन क्षेत्र द्वारा उनके द्वारा अविश्वसनीय किसी निर्दिष्ट</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अनुक्रमांक</td>
<td>अनुच्छेद</td>
<td>कमी/घट</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>एलेंसी ह्वारा सूचना प्रायोगिकता की इकाई प्रभावित किया गया है।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>टिप्पणी—यह घट केवल मध्यप्रदेश सूचना प्रायोगिकता नियंत्रण नीति, 2012, यथासंबंधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश संविधान विभाग संस्थान आवेदनसिहित/ विभाग संस्थान प्रमाण (बोपोट/बोपोट) उद्योग नियंत्रण नीति, 2014 के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>सूचना तथा लघु उद्योगों की दशा में तथा आवासीय प्रयोजन के लिए दस करोड़ रुपए तक के ऋण को प्रतिपुरूढ़ करने के लिए एक बिलेटों के निषेध से संबंधित करार की लिखित पूरा पर रीति प्रभाव सुलक्षण करता है 0.125 प्रतिशत किया जाता है।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>मुख्यमंत्री सार्वजनिक आवास योजना के अंतर्गत आवासगृह निर्माण के प्रयोजन के लिए उसके चारा प्रायोगिक एक लंबी समय तक के ऋण या अंदाज़ का प्रतिलिपि सुनिश्चित करने के लिए, किसी वैक या यथासंबंधित संस्था के प्रयोजन में किसी हिताहित द्वारा निर्माण किया है या विशेष रूप से संबंधित विधान अथवा प्रमाण सुलक्षण से हुए या सुलक्षण के तहत अधिनीय किया जा सकता है ।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>विभिन्न प्रकार के साथ संबंधित आवास पत्र पर।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>कृपया उच्चार के प्रयोग या निश्चित के किसी सिलाई पर, यदि वह अनुप्रभावित हो।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>अनुच्छेद—9—अ अनुक्रम या मूल्यांकन।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>अनुक्रम या मूल्यांकन, जो केवल एक पहलात की जानकारी के लिए किया गया है, और जो या तो करार या विधि के प्रवर्तन द्वारा पहलातों के बीच किसी भी रीति से वास्तविक नहीं है।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>भाषाक के रूप में भूमिकाम्य को दी जाने वाली रक्षा अभिनिर्दिष्ट करने के प्रयोजन में रेटार्ड को अपने संबंधित विधान पर।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>अनुच्छेद —10—सिद्धांत सिद्धियार्थ—</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>शिल्प अभिनियम 1961 (1961 का 52) के अंतर्गत किसी व्यक्ति या अन्य सिद्धांत के संरक्षण द्वारा किसी नियोजक के अधीन में निर्माण संबंधित संरक्षण पर।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>शिल्प निर्माण, जिसके द्वारा कोई या अधीन किसी व्यक्ति या उसके प्रभाव में शिल्प रखा गया हो।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>अनुच्छेद—14—बंध पत्र</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>संभाव्य है कि किसी व्यक्ति द्वारा यह गार्डों के प्रयोजन के लिए निर्माण किया गया हो कि किसी पूर्व रीति-पत्र को या विधानसभा को या लोक उपयोगी उद्देश्य के लिए किसी अभिनियम से प्रताप श्रेष्ठीय आय प्रतिभित एक निर्दिष्ट रासम से कम नहीं होगी।</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>अनुच्छेद—16—र दंडकरण</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>संभाव्य है कि लोग के दंडकरण की लिखित पर।</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>अनुच्छेद—25—हस्ताक्षर पत्र—</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>संभाव्य है कि लोग के दंडकरण की लिखित पर।</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अनुक्रमक</td>
<td>अनुच्छेद</td>
<td>कमी/छूट</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
<td>------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(भूखपण द्वारा मूल्य को छींककर) नियमादित विक्रय के लिए दरों पर प्रभाव रत्नागिरी छुक्की की दरों में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत रहते हुए कमी/छूट रहेगी : —

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समूह तथा मध्यम आय वर्ग—समूह के प्रवर्तकों के खर्चों/प्रक्रियाओं के लिए कमांड: 100 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रभाव रत्नागिरी छुक्की में छूट/कमी की जाएगी, किन्तु उच्च आय वर्ग के खर्चों/प्रक्रियाओं के नामों में कोई छूट/कमी नहीं की जाएगी ;

(ख) यह छूट/कमी केवल स्थ-वित्तीय योजना के अंतर्गत मूल आपूर्तियों तक सीमित रहेगी।

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग समूह तथा मध्यम आय समूह से वही आर्थिक होगा, उस प्रशासन तथा प्रयोजन विभाग द्वारा समय-समय पर परिभाषित तथा निर्देश किया जाएगा:

पर्युत भागत निर्मित मकान/प्रक्रिया की दर में यह छूट उपलब्ध नहीं होगी।

2. अनुसूचित जनजाति के किसी बालक द्वारा उसके जीवनकाल में उसके किसी विभिन्न पारिस/वारिसों के पास में नियमादित कुमुड भूमि के सभी प्रकार के अंतर्गत वित्तों पर।

3. मत्यप्रदेश राज्य में स्थापित किये जाने वाले सूचना प्रौद्योगिकी/बीडियो उद्योगों के पास में राज्य सरकार या किसी अन्य शासकीय संस्था या किसी शासकीय उपकरण की ओर से नियमादित भू-सूक्ष्म या निर्मित जगह से संबंधित विक्रय की लिखाओं पर।

4. ओपनसोक इकाइयों के चाँदू समुदाय के रूप में हस्तांतरण के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी/बीडियो कंपनी के किसी नई इकाई/वित्तारित इकाई/आधुनिकीकृत इकाई के पास में भूमि/परिसर अंतर्गत की जाएगी है, पर स्टाम्प हुकुम से छूट इस दर के अंतर्गत रहेगी कि नई इकाई/वित्तारित इकाई/आधुनिकीकृत इकाई को मत्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नियोजन नीति, 2012, उपपालित 2014 अथवा मत्यप्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी आवाससेंटर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग (बीडियो/बीडियो) उद्योग नियोजन नीति, 2014 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा या उनके द्वारा अभियुक्त किसी निर्धारित एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी/बीडियो इकाई प्राप्त किया गया हो।

5. वित्तीय संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों या निजी क्षेत्र द्वारा या उनकी ओर से नियमादित विक्रय के लिए दरों पर जिनके द्वारा कि सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी/बीडियो कंपनी के किसी नई इकाई/वित्तारित इकाई/आधुनिकीकृत इकाई के पास में भूमि/परिसर अंतर्गत की जाएगी है, पर स्टाम्प हुकुम से छूट इस दर के अंतर्गत रहेगी कि नई इकाई/वित्तारित इकाई/आधुनिकीकृत इकाई को मत्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नियोजन नीति, 2012, उपपालित 2014 अथवा मत्यप्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी आवाससेंटर विज्ञान प्रौद्योगिकी (बीडियो/बीडियो) उद्योग नियोजन नीति, 2014 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा या उनके द्वारा अभियुक्त किसी निर्धारित एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी/बीडियो इकाई प्राप्त किया गया हो।

दिशापूर्वी—यह छूट केवल मत्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नियोजन नीति, 2012, उपपालित 2014 अथवा मत्यप्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी आवाससेंटर विज्ञान प्रौद्योगिकी (बीडियो/बीडियो) उद्योग नियोजन नीति, 2014 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा या उनके द्वारा अभियुक्त किसी निर्धारित एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी/बीडियो इकाई प्राप्त किया गया हो।
<table>
<thead>
<tr>
<th>कृति/छोटा</th>
<th>तिथि/निम्नता</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>विजेन्द्र प्रसाद प्रधान (बीपी.पी.ई.) उद्योग निदेश नीति, 2014 के प्रवर्तन में रहने तक हो लागू रहेगी।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6. उन व्यक्तियों, जिनकी भूमि आदाय हेडेंट ट्रेक परियोजना, धीमपुर, जिला धार के लिए अर्जित की गई हैं, के पास में नियमित विवाद की गई विवेचना विलेख के प्रमाण स्टाम्प शुल्क में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छोटा रहेगी —</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(क) धार जिले के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रमाण के प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है जिसके आदाय हेडेंट ट्रेक परियोजना, धीमपुर के लिए भूमि अर्जन के लिए सांदर्भिक मुआवजा की रकम के साथ-साथ विवेचना पुनर्लेख अनुदान की रकम का उल्लेख हो।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ख) उन मौजूद (क) की स्थिति विवेचना विलेख में अभियंता की गई है, तथा</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ग) छोटा की पात्रता मुआवजे तथा विवेचना पुनर्लेख अनुदान की रकम पर प्रमाण स्टाम्प शुल्क की राशि तक निराकरित होगी</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(घ) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के उपर्युक्त के अनुसार ऐसी लिखित पर प्रमाण स्टाम्प शुल्क की, वाणिज्य, उद्योग और सेवाएं विवाद द्वारा लिखित के रजिस्ट्रीकरण को दिनांक से एक माह के भीतर वाणिज्यिक कर विवाद को प्रतिपुर्वत की जाएगी।</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रमाण-पत्र</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>कमांडर</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रमाणित किया जाता है कि श्री</td>
</tr>
<tr>
<td>की भूमि क्षेत्रफल हेडेंट, ऑटो टेस्टिंग ट्रेक परियोजना, धीमपुर, जिला धार के लिए अर्जित की गई है, जिससे लिए संदर्भ की गई मुआवजा एवं अनुदान राशि का विवरण निम्नानुसार है।</td>
</tr>
<tr>
<td>मुआवजा राशि विवेचना अनुदान राशि योग</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. यह प्रमाण-पत्र श्री द्वारा श्री पिता श्री |
| के पास में नियमित द्वारा की भूमि क्षेत्रफल हेडेंट की भूमि क्षेत्रफल पर प्रमाण स्टाम्प शुल्क से छोटा विवरण करने के लिए लागू होगा। इस रजिस्ट्री के उपरान्त स्टाम्प शुल्क से छोटा की राशि की पात्रता, शेष मुआवजा एवं विवेचना पुनर्लेख अनुदान की कुल राशि रू पर प्रमाण स्टाम्प शुल्क की राशि तक ही उल्लेख होगा। किंतु किसी भी दशा में स्टाम्प शुल्क से छोटा की राशि श्री आत्मज श्री द्वारा प्राप्त की गई मुआवजा राशि एवं विवेचना पुनर्लेख अनुदान के योग की राशि पर प्रमाण स्टाम्प शुल्क से अधिक नहीं होगी। |

7. निम्न व्यक्तियों द्वारा अपारंपरिक रूप से विवेचन उपर्युक्त करने के लिए राखी दी गई उद्योग के रूप में नियमित की गई विवेचन की लिखितों पर प्रमाण स्टाम्प शुल्क को किया करने नियमित किया गया है। |

कलन्कर, धारा
<table>
<thead>
<tr>
<th>अनुक्रमांक</th>
<th>अनुक्रम</th>
<th>कानी-छूट</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

अभ्योजन रहते हुए, आश्री की जारीगी —
(क) इकाई द्वारा इस आदेश के अभ्योजन छूट दी गई स्टेंड शुल्क की रकम के बहावर शासक, बैंक गराउन दो, पत्रक रजस्त्र या लोर रजस्त्र परियोजना की दरा में 21 मास की कालवधि तथा बैंकगार्टन या नगरीय अधिशिष्ट परियोजनाओं के लिए 38 मास की कालवधि के लिए, राज्य सरकार के प्रश्न में दी जाएगी।
(ख) यदि परियोजना बैंक गराउन दो दी गई कालवधि के भीतर स्थापित नहीं की जाती है, तो छूट प्राप्त स्टेंड शुल्क की एकम सरकार को संदाय करने का अधिकार उस इकाई का होगा। इकाई का यह भी उल्लेख दायित्व होगा कि वह स्थापित कालवधि समाप्त होने के पूर्व इस निमित्त उन्म विभाग द्वारा नियुक्त, जिसे वास्तविक प्राधिकृत से एक प्रमाण-पत्र संबंधित किया; जिससे कि कद की गई भूमि स्थित है, के जिला ग्रामीण तर के समस्त प्रस्तृत कर्म के बैंक गराउन दो में स्थित कालवधि के पूर्व इकाई स्थापित की जा सकी है। आरोपम के दशा में वह छूट प्राप्त की गई शुल्क की रकम, इकाई द्वारा इस प्रयोजन के लिए दी गई बैंक गराउन दो से वसूली योजना होगी।

8. पांड के विकासकार्य द्वारा किसी इकाई प्रस्तृत इकाई के प्रश्न में फुट पांड में यह निमित्त भूमि के अन्तर्गत हेतु नियुक्त लिखित पर
निमित्त गठित संगठन के अभ्योजन रहते हुए छूट रहती—
(क) उपलब्ध भूमि के कारण इकाई के लिखित पर मान्यता शुल्क का समाप्त होने अन्तर्गत भू-भूमि के अनुपात में किया जाएगा; और
(ख) यदि समाप्त के अनुसार कोई शुल्क संदेह किया जाना अपेक्षित नहीं हो, तो अन्तर्गत के लिये न्यूनतम शुल्क केवल पांड को देने रूप नहीं होगा।

9. मध्यप्रदेश गृहपालन एवं पशुधन संवेजन सिधेक नोपाल द्वारा पर्यावरण किसी गृहपालन तथा पशुधन के फसल में निमाजित भूमि के विवध की लिखित पर।

10. मध्यप्रदेश स्थानीय निगम गृहपालन, नगर विकास प्राधिकृतों, नगर भवन निगम सहकारी समितियों, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आयुक्त अध्यक्ष मध्यप्रदेश में रहकर किसी नगरीय स्थानीय निगम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किसी विवध के प्रयोजन में निमाजित विवध के लिखित पर।

"आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से वैकल्पिक आशय होगा, जैसा नगरीय प्रशासन विवध द्वारा समय-समय पर प्रतिवर्तित तथा योजित किया जाएगा। जिला कलन्दर द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

स्टेंड शुल्क से उस दानने में भी छूट प्राप्त रहनी जहां आवासीय भवनों के पाठ की लिखित शासक गृहपालन के लिये वृद्धियों मुक्त (शैख़ा.मुमू) / एक्रकृत आवास और विकास कार्यक्रम (आईएसएसेकृत) के अन्तर्गत किसी ऐसे विवध के प्रयोजन में निमाजित की जाती है, जो मध्यप्रदेश नगरीय केन्द्रों के भूमीधन व्यवस्था (शैख़ा.मुमूटिकार्य) के द्वारा विवध के प्रयोजन द्वारा निमाजित किए गए प्रश्नों के साथ।
| अनुक्रमक | अनुच्छेद | कमी/छुट्
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
11. सरकार या किसी अन्य शासकीय संस्था या किसी सरकारी उपक्रम या
| | | तत्त्वाधीन प्रवृत्ति किसी विषय के अभीन्न रूपों का लिखित मूल्यांकन सहकारी समिति द्वारा या उसकी ओर से निर्धारित किसी रूप निर्मित सहकारी समिति द्वारा या उसकी ओर से निर्माणित निर्देश में अनुसार नवीनित्रित अधिकारी का नवीन-होन अधिकारी की संपरिसंधि करने से संबंधित हस्तांतरण की लिखित पर स्वाम शुल्क कम करते हुए केवल लिखित में यथा उपकेलित संपरिसंधि के साथ संबंधित प्रतिष्ठित की रकम पर ही प्रमाणात होगा, किन्तु किसी भी दशा में प्रमाण शुल्क का रकम पांच से कम नहीं होगी।
12. ऐसी बीमार/बंद आयोगिक इकाइयों के, जो कि आयोगिक वित्त एवं
| | | पुनर्निर्मित कोई (बीआईपीआई) या किसी परिसंपादक को निर्धारित की गई हो, या वित्तीय संस्थाओं या बंदों द्वारा अभिगृहीत की गई हो या जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा परिभाषित बीमार उद्योग की अभी या अभित्व हो, विवरण की संपरिसंधि पर प्रमाण प्रमाण शुल्क से इन रकमों के अभित्व रहते हुए प्रमाण की जाती है—

(एक) छुट केवल एक बार प्रदान की जा सकती। उन
| | | इकाइयों/अभिनव के हस्तांतरण पर, जिन पर कि इस अधिसूचना के
| | | अभिनव एक बार प्रमाण की जा दी जा सकती है, किसी भी दशा में दुरारी
| | | छुट प्रदान की जा सकती है; ध्यान में रखें कि ऐसे बंद के लिए, संख्या
| | | पुनर्निर्मित आयोगिक इकाई के प्रदान की
| | | जाएगी जिन निर्देशों के स्वाम शुल्क से, छुट केवल देने का निर्णय, भारत
| | | वर्तमान संवर्तन नीति, 2010, व्यापार संवर्तन 2012 अथवा भारत
| | | वर्तमान संवर्तन नीति, 2014 तथा उसकी कार्यवाही के पुनर्निर्माण एवं
| | | अभिनव को लिखित द्वारा यथा परिभाषित भारत
| | | वर्तमान संवर्तन के मुद्य संस्थान की अभित्वात्मक
| | | अभिनव के संबंधी कार्यक्रम संगठित द्वारा यथा परिभाषित भारतीय मुद्य
| | | संस्थान की अभित्व या उनके कार्यक्रम की अभित्व
| | | अभिनव संबंधी कार्यक्रम संगठित द्वारा यथा परिभाषित भारतीय मुद्य
| | | संस्थान की अभित्व।

(तौरे) छुट प्राप्त करने के लिए इकाइयों के केंद्र का समाहार प्रबंधक के
| | | स्वाम उसके विनिमय यथिक्ष्ठ का स्वाम करते हुए इकाइयों के
| | | पुनर्निर्मित को देना अद्यतन करना होगी। केंद्र का समाहार प्रबंधक के
| | | स्वाम यह लक्ष्य बनाना देगा होगा कि यह भारतीय मुद्य संस्थान में
| | | पुनर्निर्माण अथवा इकाइयों के स्वाम की रकम के
| | | उन्नयन के लिए निदेशात्मक की तारीख से प्रत्येक के
| | | उनके किसी भी निदेश के लिए अभित्व, की दर से समाहार लिखित
| | | अभित्व रहता रहेगा। पुनर्निर्माण के लिए, उन विधिविधिक कार्यक्रम के विवरण
| | | का उपयोग करने का पात्र होगा; और

(बारं) छुट, समाहार प्रबंधक के के इस आश्वासन या प्रमाण या
| | | अभिनव के हस्तांतरण पर हुए प्राप्त होगी कि निर्मान के.
| | | इस अभिनव का अभिनव प्रथम के प्राप्त करने का प्रथम तलह है।उनका प्रमाण पुनर्निर्माण जारी करने के लिए
| | | प्रबंधक के समाहार प्रबंधक की निदेशात्मक होगी—
| | | इकाइयों का मुद्य/बाजार मुद्य
| | | समाहार प्रबंधक

(पूर्व) इशारा एक करोड़ रुपए से अधिक न हो: संबंधित जितने का कलक्टर
(दो) जहां एक करोड़ रुपए से अधिक हो: संबंधित संग्रह का
<table>
<thead>
<tr>
<th>अनुक्रमांक</th>
<th>अनुष्ठान</th>
<th>कमी/छूट</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(2)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(3)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

13. आधुनिक इकाईयों के बालू समुदाय के तुल्य में, विकास या विलयन या प्रामाण्य को घटाकर अवधारणा दसमाह रूप से उस रिपोर्ट में किया जाएगा, जबकि प्रामाण्य शुल्क किसी भी रूप से अधिक हो। शुल्क में यह कमी निम्नलिखित शर्तों के अनुसार रहती हैं: 

(क) उत्कृष्ट उद्योग के खेतर क्षमता उपयोग हेतु निम्नाधिकता की गई हो।
(ख) उद्योग की उपत्यका ठीक पूर्ववर्ती पारदर्शक तथा न्यूनतम क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।
(ग) फ़िल्टर को नियोजन संस्थान निजी उद्योग की रणनीति दिखाई दें है।

उन्होंने इस क्रिया को ठीक पूर्ववर्ती दो दर्शक के लिए नाम-परामर्श देने एवं समीक्षा माना गया है।

(ह) उद्योग का शुल्क मूल्य घटकर ठीक पूर्ववर्ती पारदर्शक तथा उसके शुल्क मूल्य से अधिक से कम रह गया है; और

(ड) उस दर्शक में, जहाँ उद्योग का विकास मूल्य एवं अवधारणा से अधिक नहीं है, संयुक्त जिले के ललितकाल द्वारा अन्य मामलों में संयुक्त संबंध के आधुस्थ द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है कि लिखत इस अवधारणा के अधिश्रुतिन अनुसार का प्रमाण रखते हैं।

टिपणी — इस अवधारणा के अधीन छूट केन्द्र मध्यप्रदेश उद्योग संबंधी 2010-2012 वित्तार्थक कार्यक्रम में रहते हैं।

14. पूर्व उच्चतर मध्यप्रदेश तकनीकी विद्यालय, राहौल के परिसर में की 12,713 एकड़ तथा आयुक्त जिले में ग्राम कल्याण पुर शासकीय सर्वे नं. 556/1 की हैटम मूल्य के, राजीव गांधी प्रोत्साहनी विद्यालय, भोपाल को हेतु एक रक्षक संस्था, सूचना सेवाओं इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए, राजीव गांधी प्रोत्साहनी विद्याविकास, भोपाल के पश्चिम में निम्नाधिकता के जाने वाले हस्ताक्षर विशेष पर।

15. ग्राम गाँवस्केप, लहल निशान निधि की भूमि के फार सर्वोत्तम अधिश्रुति 188/3 के 8,359 हेक्टर क्षेत्र में से 7,422 हेक्टर क्षेत्र, सर्वोच्च कमांड 116 के 0.063 हेक्टर क्षेत्र, सर्वोच्च कमांड 117/1 के 2.023 हेक्टर क्षेत्र तथा सर्वोच्च कमांड 138 के 1.517 हेक्टर क्षेत्र में से 0.612 हेक्टर की भूमि 12,120 हेक्टर (25 एकड़) भूमि के, राजीव गांधी प्रोत्साहनी विद्याविकास की घटक संस्था, सूचना सेवाओं इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कृतिस्थापन, सिद्धांत विश्वास की स्थापना के लिए, राजीव गांधी प्रोत्साहनी विद्यापीठ, भोपाल के पश्चिम में निम्नाधिकता के जाने वाले हस्ताक्षर विशेष पर।

16. अनुपूर्ण जिले में मेसर्स स्थ जोर्ड मैकेवर्क लिमिटेड द्वारा ताल वियोजन के साथ-साथ एवं और निम्नाधिकता के अधिश्रुति/ प्रामाणित प्रशिक्षण के अनुसार देने प्रति प्रति जिले तक की भूमि के कम विशेष पर ग्राम कल्याण पुर स्थल से निम्नाधिकता शर्तों के अधिश्रुति प्रदान हेतु छूट दी।
<table>
<thead>
<tr>
<th>अनुक्रमांक</th>
<th>अनुच्छेद</th>
<th>कमी/घट</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

प्रदान की जाती है, अथवा –

(क) इस परियोजना हेतु पुनर्वास पैकेज की औपचारिक स्वीकृति, समाप्ति रक्तमशीन शूलक की शीर्षकृति हेतु आवश्यक रक्त जिला कलेक्टर द्वारा होने के लिए निर्देशित राजस्थान शीर्ष में जमा कराने के प्रयास जारी की जाएँ

(ख) इस परियोजना के पुनर्वास पैकेज के अधीन प्रदान के विश्वासद विषय विवाह अधिकार के अंदर एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जिसमें विश्वासद के नाम प्रति प्रति की रक्त देने से सम्बन्धित विवेश पुनर्वास अनुदान की हून का उल्लेख किया जाएगा।

(ग) इस परियोजना के अधीन रक्तमशीन शूलक के अधीन प्रदान के रक्त शूलक की प्रति प्रति की रक्त शूलक का उल्लेख किया जाएगा।

(घ) रक्तमशीन शूलक के अधीन प्रदान के रक्त शूलक का उल्लेख किया जाएगा।

(घ) रक्तमशीन शूलक का उल्लेख किया जाएगा।

17. नर्मदा घाटी परियोजना के कारण विश्वासद तथा बिवेश पर निर्देशित शरीर देने के अधीन रहने हुए छुट को हेतु प्रदान की है, अथवा –

(क) परियोजना के क्षेत्र भू-अर्जन अधिकारी के प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया गया हो, जिसमें उनके भू-अर्जन अनुभव में सम्मिलित समय के लिए बाल वर्णित नामकृति उपलब्ध है।

(ख) विश्वासद की राशि को समन्वित नहीं किया जाएगा।

(ग) विश्वासद के अधीन प्रधान मंत्री का समन्वित नहीं किया जाएगा।

(घ) विश्वासद के अधीन प्रधान मंत्री का समन्वित नहीं किया जाएगा।

(घ) विश्वासद के अधीन प्रधान मंत्री का समन्वित नहीं किया जाएगा।

(घ) विश्वासद के अधीन प्रधान मंत्री का समन्वित नहीं किया जाएगा।

(घ) विश्वासद के अधीन प्रधान मंत्री का समन्वित नहीं किया जाएगा।

(घ) विश्वासद के अधीन प्रधान मंत्री का समन्वित नहीं किया जाएगा।

(घ) विश्वासद के अधीन प्रधान मंत्री का समन्वित नहीं किया जाएगा।
<table>
<thead>
<tr>
<th>अनुक्रमक</th>
<th>अनुच्छेद</th>
<th>कर्मी/घटक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(3)</td>
<td>ऐसा भूमिशीलन विश्लेषण व्यक्ति एवं जगत कुट्टा भी जो पुर्णवास्क अनुभाव, उद्योगकर्ता सम्पत्ति के कारण से लेकर दी जाने वाली विचित्र सहायता, पुर्णवास्क स्थान के कारण से विविध आवासीय मुद्दत एवं जो दी जाने उद्योगकर्ता सहायता के रूप में फायदा हिस्सेदार राशियों से कृपिया मूल्य लब्ध / या अन्य अवधारणा सम्पत्ति कारण सहायता का है, भी उक्त प्रदेश के लिए हकदार होगा।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18. नियमितता के लिए नियमावधि की गई शिखरों पर—</td>
<td>क) ग्रामपंचायत राज्य में दिल्ली–पुर्णवास कुलदुर्ग दोर्डोर्डो दुर्गाधर द्वारा आयुक्त उदय तथा विविध उद्योगपुरी परियोजना की स्थापना के लिए गठित स्थानीय अंतर्गत अभियंतार उदय को लाभ, राज्य सरकार के वाहिनी, उदय रोजगार सरकार द्वारा अधिनियम के हस्तांतरण हेतु नियमावधि स्थिर किए पर।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(क) प्रदेश के लिए उद्योगकर्ता विविध उद्योगपुरी परियोजना के मार्गदर्शन ज्ञान के लिए किसी विकासकर्ता, अंतर्गत, नियमित कम्युनिटी या संयुक्त उद्योग को ऐसी भूमि के किसी खण्ड के केंद्र से प्रमुख योजना हस्तांतरण के लिए नियमावधि स्थिर किए पर। यह राज्य किया जाता है कि इस प्रयोजन के लिए अन्य अवधारणा द्वारा आयुक्त नहीं किया गया प्राप्त।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 प्रतिलिपियाधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) के अधीन प्रतिलिपियाधिकार का समन्वय।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>अनुच्छेद—26–प्रति या उद्धरण—</td>
<td>1. किसी ऐसे कर्मचारी–पिल की प्रतिलिपि इससे संबंध में किसी लोक अधिकारी से विविध द्वारा अधिनियम या लघु समावेश या लघु प्रयोजन की नियमित अवधारणा के लिए उसे बनाए या दे।</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>अनुच्छेद—27–प्रतिलिपि या दूसरी प्रति</td>
<td>कृपया को दिये गए किसी प्रदेश का प्रतिलिपि जो ऐसा पदद्वार शुल्क से घटा प्राप्त हो।</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>अनुच्छेद—34–संपत्ति का विनियम</td>
<td>दो हेडेंगर तक कृपिया भूमि के विनियम का विनियम के संबंध में प्रभावित स्थापना शुल्क से नियमित शारीरिक से अभिनेता घट होगी।</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 12. | अनुच्छेद—35–आत्मिक पाल | 1. किसी भूमिपाल के रूप में भूमिपाल करने वाले व्यक्ति द्वारा कृपिया प्रयोजनों
<table>
<thead>
<tr>
<th>अनुक्रमांक</th>
<th>अनुच्छेद</th>
<th>क़पड़ी/छूट</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 13.       | अनुच्छेद-36 -दान की लिखत | 1. राज्य सरकार के पत्र में निर्दाहित दान की लिखत पर।  
|           |         | 2. मध्यभारत गौरीतल एवं पशुधन सर्वेक्षण बोर्ड, भोपाल द्वारा पंजीकृत किसी गौरीतल के पत्र में निर्दाहित भूमि के पत्र की लिखत पर।  
|           |         | 3. अनुपूर्वित जनजाति के किसी व्यक्ति द्वारा जीवनकाल में उसके किसी विशेष वारस/वारसों के पत्र में निर्दाहित कृषि भूमि के सम मंथन के अध्याण विषयों पर। |
| 14.       | अनुच्छेद-37 - कृषिपूर्ति बंध पत्र | कोलाहल खान भविष्य निधि के मृत सदस्यों के अन्य वस्तुओं के संबंध में उसकी संबंधित निधि का रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये निर्दाहित किये जाने वाले कृषिपूर्ति बंध पत्र पर। |
| 15.       | अनुच्छेद 38 -पद्धत | 1. व्यवसायी इंजीनियर को वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा उनके उनका स्वरूप का उद्योग बदलने के लिये अवश्य सुविधायों और उपकरणों के संबंध में आवेदित की गई भूमि तथा निर्मित बंध के संबंध में उनके द्वारा निर्दाहित पद्धति द्विशेष पर। स्टांप शुल्क से छूट निर्मितित किए गए बंधों के अध्यायन से, अर्थात् -  
|           |         | (क) आवेदक या उसकी फ़र्म के समस्त वहीनार डिप्टी अथवा डिलीगेशन इंजीनियर हो; और  
<p>|           |         | (ब)आवेदक या उसकी फ़र्म को समस्त आय और उसके ग्राम या पिता की आय के एक हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं हो। |
|           |         | 2. सरकार द्वारा मध्यभारत परियोजना निर्माण के पत्र में निर्दाहित ऐसी भूमि के संबंध में जिन पर कि उनके निर्माण की इकाियां स्थित हैं, के पद्धति की लिखतों पर। |
|           |         | 3. मध्यभारत राज्य के परियोजन निर्माण द्वारा परियोजना परियोजनाओं के लिए निर्दाहित किए जाने वाली शास्त्रीय भूमि के पद्धतियों की लिखतों पर। |
|           |         | 4. मध्यभारत राज्य ने स्थापित किये जाने वाले सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के पत्र में राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन या किसी शास्त्रीय उद्योग की ओर से निर्दाहित गू-घूड़ (स्टांप) या विनिमयित जमाने से संबंधित पद्धति की लिखतों पर। |
|           |         | 5. मध्यभारत सहकरी समिति अधिनियम, 1960 (1961 का 17) के क्रमांक रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समस्त गई महुआ सहकारी समिति के पत्र में दो हजार हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल वाले जलवायु से मल्लीक पकड़ने से संबंधित पद्धति की लिखत पर। |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>अनुक्रमांक</th>
<th>अनुच्छेद</th>
<th>कमी/घटक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6. किसी जलाशय से मछली पकड़ने के लिए मछली या मछुआरों के पक्ष में किसी ग्राम पंचायत द्वारा नियामित पदटा विलेख पर。

7. वित्तीय संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों या निकी क्षेत्र द्वारा या उन के अंतर्गत से किसी एजेंसी द्वारा दूरबीन लक्षणों की अतिरिक्त विशेषता की जाकर दूरबीन लक्षणों की नियमित सुरक्षा क्षेत्र में सुरक्षा में प्राथमिकता/बी.जी.आई. कम्पनी की किसी नई इकाई/विस्तारित इकाई/आर्थिककृत्त इकाई के पक्ष में भूमिका/परिस्थिति अंतरित की जाती है, पर स्थान शुल्क से छुट्टी इस शर्त के अंतर्गत रखनी जब तक कि उसे मध्यप्रदेश सूचना प्राइवेसी नियोजन नीति, 2012, अनुसार किया जाता है।

8. मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य एवं उद्योग तथा रोजगार विभाग या मध्यप्रदेश अधिकारी क्षेत्र विकास निगम द्वारा, जली-जली या आपूर्ति पर विभाग रोजगार उद्योगों के पक्ष में उद्योग के नाम में परिवर्तन, भारतीय/भारतीय के उसमें जोड़ने, सहयोग या उसके पुनर्निर्माण के कारण नियामित पदटा के संबंध में निकटता की जाती है।

9. (क) अधिकारी इकाई मध्यप्रदेश सत्तवार या मध्यप्रदेश अधिकारी क्षेत्र विकास निगम द्वारा विफलित किया गए अधिकारी क्षेत्र या अधिकारी वृक्ष (प्रोफ़) केन्द्र में स्थित है; और

(ब) आयुक्त, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस आरोप का एक पात्र प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि, यह उद्योग स्टाइप शुल्क में छुट्टी के लिए पात्र है।

(क) अधिनियम केन्द्र मध्यप्रदेश उद्योग सत्तवार नीति, 2010, अनुसार किया गया जो मध्यप्रदेश उद्योग सत्तवार नीति, 2014 तथा उसकी कार्यों योजना के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू होगी।

9. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, नगर विकास प्राधिकृतों, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आयात संघ अथवा मध्यप्रदेश में स्थित किसी राज्यीय व्यापार नियोजन द्वारा आर्थिक रूप से कम्पनी वर्ग जैसा नागरिक प्रशासन तथा व्यापारिक विभाग द्वारा समय-संगठन पर परीक्षण तथा निर्देशित किया जाए। किसी व्यक्ति के पक्ष में नियामित पदटा जिला कार्यालय से, इसे आरोप का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(द) जलसंसाधन से उत्पादक में भी छुट्टी प्रदान की जाएगी जहां आरक्षण नियमों के अंतर्गत जल संसाधन लगा जाने के लिए बुनियादी सुविधा (प्रीएस्प्लॉट) एवं विकास अधिकारी क्षेत्र विकास (आईएसएससी) के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नियामित की जाती है, जो मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिक्षण व्यक्ति (फैसलावद)
<table>
<thead>
<tr>
<th>अनुक्रमांक</th>
<th>अनुच्छेद</th>
<th>कमी/घट</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10.</td>
<td>राज्य सरकार द्वारा या उसके किसी उपकरण द्वारा या उसकी ओर से नियामित औद्योगिक क्षेत्रों तथा औद्योगिक विकास केंद्रों में भूमि और वस्तुओं के पट्टों में संशोधन की लिखित प्रयास शुल्क कम करते हुए केवल निर्धारित अंतरराष्ट्रीय संबंध शुल्क की रकम पर ही, उसे पट्टे के लिये बाजार मूल्य की रकम मानते हुए, भावः होगा: परन्तु प्रथम प्रारंभिक नामले में पक्षकारों द्वारा उस संबंधित प्रयोग के, जिसमें कि भूमि निर्मित है, रचना कलकार का इस आरोप का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि उस लिखित पर, जिसके का आरोप पर सरकार या सरकार के संबंधित उपकरण द्वारा पट्टे में संशोधन की अनुमान दी गई थी, सम्बन्धित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| तिथि: | यह घट केवल मध्यप्रदेश उद्योग संबंधन नीति, 2010, यथासंशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संबंधन नीति, 2014 तथा उनकी कार्य संस्थान के प्रयासों में रहने तक ही लागू रहेगी। |

| 11. | ऐसी बीमार/बंद औद्योगिक इकाइयों के, जो कि औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बैंक (बैंकईफायर) या किसी परीमाणधिक को मिलेंगी की गई हो, या बिल्कुल संतुलित या वैदिक इकाइयों द्वारा अभियुक्त की गई होंगे या जो भारतीय विदेशी बैंक द्वारा यथासंशोधित बीमार उद्योग के क्षेत्र में आती हैं, पट्टे की लिखित प्रमाण-पत्र स्टाम्प शुल्क पर निर्माण शर्तों के अध्ययन रहते हुए घट रहेगी। |

| (क) | घट केवल एक बार प्रदान की जाएगी। उन इकाइयों/आस्थियों के हटाने पर जिन पर कि इस अविश्वसन के आधार पर एक बार घट प्रदान की जा चुकी है, किसी भी दशा में दुरारा घट प्रदान नहीं की जाएगी। |

| (ख) | घट केवल ऐसी बंद और बीमार इकाइयों को प्रदान की जाएगी। जिसको कि स्टाम्प शुल्क से घट देने का निर्णय, मध्यप्रदेश उद्योग संबंधन नीति, 2010, यथासंशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संबंधन नीति, 2014 तथा उसकी कार्यों के उपकरण के अवधी गतिविधि, यथासंशोधित मध्यप्रदेश राज्य के मूल शर्तों की अवधिकार वाली उच्च अविश्वसन प्राप्त संविधि द्वारा या जिले के कलेक्टर की अधकार वाली संविधि संविधि द्वारा किया गया हो। |

| (ग) | घट प्राप्त करने के लिए इकाइयों के पट्टे दारक को सक्षम प्राप्त करने के समय उसकी विलीनता शिल्प को स्पष्ट करते हुए इकाइयों प्रमाण-पत्रों देने की जिम्मेदारी होगी। पट्टे दारक को सक्षम प्राप्त करने के समय यह उवचार भी देना होगा कि यह उद्योग को उद्योग माह में पुनर्विश्वसन करेगा और उसके उत्तरार्ध में दशा में स्टाम्प शुल्क से दी गई घट की रकम का लिखित के निर्माण की तारीख से प्रतिमाह या उसके किसी भाग के लिए 0.75 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से भुगतान करेगा। पुनर्विश्वसन के लिए यह विलीनक्रम के विकल्प उपयोग करने का पात्र होगा; और |

| (ह) | 
| अनुक्रमांक | अनुच्छेद | कमी/छुट्
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(१)</td>
<td>(२)</td>
<td>(३)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(प) छुट्ट, सक्षम प्राधिकारी के इस आदेश के प्रमाण-पत्र के अधीन रहते हुए प्राप्त होगी कि लिखत को, इस अभिलेखन अधीन दस्तावेज रखने की पात्रता है।

उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित गोष्टें होना आवश्यक होगा:

<table>
<thead>
<tr>
<th>दोकान का नाम</th>
<th>दानार</th>
<th>मूल्य</th>
</tr>
</thead>
</table>
| (एक) पता एक करोड़ रुपए से अधिक न हो | सामान्य संबंधित जिले का कल्याण 
| (दो) पता एक करोड़ रुपए से अधिक हो | सामान्य संबंधित समाज का संस्थानमय आयुक्त 

दशकनीय वर्ष २०१०, नया के या उसके उत्तरदायी केंद्र संबंधित नीति, २०१२ तथा उसकी राज्य सरकार के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी।

12. नर्मदा घाटी परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए किसी परिवार के सदस्य के पता में मूल्य अन्तर्भाषित करने के लिए निम्नलिखित पत्र दिलेंगे:

(क) परियोजना क्षेत्र के मूल्य-अन्तर्भाषित करने के लिए पत्र दिलेंगे जिसमें उसकी भूमिका एवं अन्य कथा सम्पूर्ण कि मध्यप्रदेश दक्षिणी राज्य में किसी पता का पूर्व भूमिका और / या अन्य कोई अन्य सम्मान का।

(ख) पत्र दिलेंगे जिसमें पिता-पत्नी की स्थिति अन्तर्भाषित करने के लिए दिखाएँ गए।

(ग) पत्र दिलेंगे जिसमें पिता-पत्नी की स्थिति अन्तर्भाषित करने के लिए दिखाएँ गए।

(घ) छुट्ट की पात्रता मूल्य लेने या सम्पूर्ण करने के लिए सम्भव या संभव पता दिलेंगे।

(ङ) पत्र दिलेंगे जिसमें पिता-पत्नी की स्थिति अन्तर्भाषित करने के लिए दिखाएँ गए।

(च) पत्र दिलेंगे जिसमें पिता-पत्नी की स्थिति अन्तर्भाषित करने के लिए दिखाएँ गए।
<table>
<thead>
<tr>
<th>अनुक्रमक</th>
<th>अनुच्छेद</th>
<th>कमी/छूट</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(13) ऐसा भूमिकान्वित विश्लेषण यात्रिक एवं व्यवस्था पुत्र भी जो पुनर्वास अनुवाद, उपादान समाप्ति के क्रम के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता, पुनर्वास स्थल पर विकसित आवासीय भूखंड के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त विभिन्न खबरों से कृप्त मुख्य तथा या अन्य अवस्था समाप्ति करना वाहता है, उल्लंघण छूट के लिए मंडलदार होगा।

13. खेतिहार की शरा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के लिए पद्धति (जिसके अंतर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए दूध का पद्धार है), जो कोई चुनना या प्रौढ़ता लिए विना या परिचालन किया विना नियमित किया गया है और जबकि कोई निर्धारित अवधि अवधारणा की गई है और ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं है या जबकि आरंभिक किया गया आसाम वार्षिक ब्लॉकके एक सी रूपये से अधिक नहीं है।

14. इस अनुच्छेद के अधीन निर्माण, प्रवर्तन और अंतर्गत (भी.ओ.टी.) योजना के अंतर्गत संकाल, पुल आदि के निर्माण पर, धोखाधड़ी करने का अधिकार देने वाले अनुसंधार पर प्रभाव इंसानी दृष्टि की दर प्रतिवर्ष एक हजार रुपये को जाती है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>16. अनुच्छेद-43—संकाल विलेख</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1. बंक का संघर्ष के अंतर्गत की पेश कत्स जो मध्यप्रदेश कान्तिना के किसी अधिकारी द्वारा अपने सवाल के निर्देश के निर्माण के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा उपभोक्ता सवाल के प्राप्त अधिकार के पुनर्प्राप्त के लिए नियमित किया गया।

2. वाणिज्य, उद्योग और खेती से विना द्वारा सरकार विज्ञापन इंजीनियरों का उन्हें उनका सवाल के उद्योग दान के लिए मध्यप्रदेश विकास निगम से एक लाख रुपये के रूप में परिवर्तन करने के लिए नियमित बंक की लिखित रूपरेखाओं पर निर्भर शाखा पर पूरा पूरी करें, अर्थात्—

(क) यूनिचेक या प्रयोग के समस्त साधारण विभीषण अध्ययन निर्माण इंजीनियर हो, और

(ख) उसकी या प्रयोग के समस्त मामलों की आय या उसके माता या पिता की आय एक हजार रुपये से अधिक नहीं है।

3. स्वामी औद्घोष एकाधिक है। विना मध्यप्रदेश विकास निगम से 7.5 लाख रुपये के तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए नियमित बंक की लिखित विना से।

4. उद्योग उद्योग का खेतिहार तत्कालीन परिक्षर के क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले किसी "मध्य पुनर्वास" द्वारा, उद्योग स्थापित करने के लिए पुनर्वास शुल्क प्राप्त बंक के प्रभावी सवाल शुल्क में कमी करते हुए पंचा लाख रुपये किया जाता है, जहां ऐसे विलेख पर देय गृही उस रूप से अधिक होता है।
5. खाली तथा प्रामाण्य आयोग एवं मध्यप्रदेश खाली तथा प्रामाण्य बोर्ड से आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए रूपण तथा अभिप्राप्ति करने के संदर्भ में राज्य के उद्योगपतियों या आध्यात्मिक उपकर्मों द्वारा नियमित किए जाने वाले कथ्य रहित बृत्त की लिखित पर।

6. नए उद्योग स्थापित करने के प्रयोजन के लिए या किसी उद्योग के हिसाब, विशिष्टकरण या आध्यात्मिककरण के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सारिके रूपण अभिप्राप्त करने के संदर्भ में सभी मध्यप्रदेश राज्य में उद्योगपतियों या आध्यात्मिक उपकर्मों द्वारा नियमित किए जाने वाले कथ्य रहित बृत्त की लिखित पर नीचे की गई सारियों में यथा-निर्देश सीमा तक छूट रहेगी —

| जिले/ ब्लक की क्षेत्री स्तम्भ शूल के छूट/कमी की सीमा |
| (मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग तथा रोजगार विभाग द्वारा किए गए विधेयक के कारण) |
| लघु उद्योग के लिए |
| मध्यम और उत्तरदेशी उद्योग के लिए |

| (1) | (2) |
| पिछड़ा “ख” | 100 प्रतिशत |
| पिछड़ा “ग” | 100 प्रतिशत |
| ऐसे ब्लक, जिनमें कोई उद्योग नहीं हो | 100 प्रतिशत |

उक्त छूट या कमी नियमित शासी के अध्यात्म रहें हए होंगी, अथवा —
(अ) लघु उद्योग की दशा में केवल उन्हीं मामलों में छूट दी जाेगी, जहाँ आपसी रूप से प्लांट एवं मशीनार्थ पर पूर्ण विविधता की रकम पांच लाख रुपए से अधिक हो तथा वह सेवा या व्यापार की क्षेत्री में न आता हो;
(ब) रूपण की सारिके रकम का यथा मध्यप्रदेश राज्य में उद्योग के विकास के लिए ही किया जाएगा ; और
(भ) आयुक्त, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार, मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस आदेश का एक पायल्ट प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो कि रूपण अभिप्राप्त करने वाला उद्योग इस आदेश के अधीन स्तम्भ शूल में कमी या छूट के लिए पत्र है।

7. सूचना प्राधिकृतिक निश्चेत्त क्षेत्र में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से रूपण प्राप्त करने के लिए सूचना प्राधिकृतिको/बौद्धिक कम्पनी की किसी नई
<table>
<thead>
<tr>
<th>अनुक्रमक</th>
<th>अनुच्छेद</th>
<th>कमी/छूट</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

इकाई / वित्तालित इकाई / आयुक्तकृत इकाई द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य इकाई रहित बंदक की सिखारी पर प्रायोजन स्टेप्स शुल्क से छूट इस शर्त के अध्यक्ष रहेंगी कि नई इकाई / वित्तालित इकाई / आयुक्तकृत इकाई का मध्यप्रदेश सूचना प्राधिकृतकृत निवेश नीति, 2012, यथासंशोधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश विज्ञापन आयुक्तसूची / विज्ञापन प्रोसेस प्रधान (बीपीएम/बीपीएम) उद्योग निवेश नीति, 2014 के अंतर्गत सूचना प्राधिकृतकृत बंदक द्वारा तथा उनके द्वारा अभियुक्त किसी निर्देश एजेंसी के संयुक्त प्राधिकृतकृत बंदक इकाई निर्देशित किया गया हो।

टिप्पणी - यह छूट केवल मध्यप्रदेश सूचना प्राधिकृतकृत निवेश नीति, 2012, यथासंशोधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश विज्ञापन आयुक्तसूची / विज्ञापन प्रोसेस प्रधान (बीपीएम/बीपीएम) उद्योग निवेश नीति, 2014 के प्रारंभ में रहने तक ही लागू रहेगी।

8. किसान कैडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण को प्रतिपूर्ति करने के लिए कुशलों द्वारा बैंकों के पार निष्पादित की जाने वाली कमान रहित बंदक की लिखायि पर।

9. नानाधर प्रायोजित स्थिरों के अधीन 10 लाख रुपये की सीमा तक समूह - सदस्यों के अधिकवकाल हेतु ऋण को प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रधान-सहायता समूहों द्वारा बैंकों के पार निष्पादित की जाने वाली कमान रहित बंदक की लिखायि पर।

10. किसी मूलभूतमानी या रेजस्ट्री बूक तक युक्तदार - चार - 3-10 के अधीन पद्दातिकों के रूप में मूलभूतमानी करने वाले व्यक्ति द्वारा कृषिक प्राप्तियों के लिए इस लाख रुपये तक के ऋण को प्रतिपूर्ति करने के लिए बैंकों के पार निष्पादित कमान रहित बंदक लिखायि पर। तथा, यह भी कि अनुसूचित जाति की अनुसूचित जाति की अंतर्गत में उच्च प्रायोजन हेतु किसी भी सीमा तक कैडिट गर्लिए स्टेप्स शुल्क देय नहीं होगा।

11. आयुक्तिक प्रयोजनों के लिए अधिनियम द्वारा भेज द्वारा व्यक्तिप्रधान प्रतिसंदृष्ट सुनिश्चित करने के लिए किसी वित्तीय संस्था के पार में फाइंस-बूक का और आयुक्त द्वारा आधारित उद्योगों द्वारा निष्पादित लिखायि पर छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्ष होगी, अथवा -

(k) आयुक्तिक इकाई मध्यप्रदेश सरकार द्वारा या मध्यप्रदेश आयुक्तिक केंद्र विचार निम्न द्वारा विकसित किए गए आयुक्तिक क्षेत्र या आयुक्तिक जुड़ि (प्रोडूज) केंद्र में रखी है। और

(ख) आयुक्तिक इकाई मध्यप्रदेश सरकार द्वारा या मध्यप्रदेश आयुक्तिक केंद्र विचार निम्न द्वारा विकसित किए गए आयुक्तिक क्षेत्र या आयुक्तिक जुड़ि (प्रोडूज) केंद्र में रखी है।

टिप्पणी - यह छूट केवल मध्यप्रदेश उद्योग संस्थान नीति, 2010, यथासंशोधित 2012, अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संस्थान नीति, 2014 तक उसकी कार्य योजना के प्रारंभ में रहने तक ही लागू रहेगी।
<table>
<thead>
<tr>
<th>अनुक्रमांक</th>
<th>अनुच्छेद</th>
<th>कमी/छूट</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

12. नुक्सानमंत्री प्रमुख आवास योजना के अधीन आवासगृह निर्माण के प्रयोजन के लिए प्राप्त होने वाले एक लाख रुपए तक के अंश या अग्रिम का प्रतिशत कम करने के लिए, किसी बैंक या वित्तीय संस्था के जवाबदेह हितादाय द्वारा निष्पादित साक्षात्कार बंधक की सिफारिश पर प्रमाण-पत्र जारी किया गया होगा जद उसे हेतु राष्ट्रीय शुल्क से छूट के लिए पत्र है।

13. मध्यप्रदेश राज्य में ऐसे नयी खाने प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए, जो मध्यप्रदेश खाने प्रसंस्करण नीति, 2008 के उपवाचन-3 में सम्मिलित दिग्गज मदद का प्रयोग करके मदान के रूप में करता है, या ऐसे उद्योग के विस्तार, विकास या अनुविकास करने के संबंध में निष्पादित किये जाने वाले क्रमा रहित शुल्क की सिफारिश पर。

14. ये लिखित जो भूमि विकास उद्यान अधिनियम, 1883 (1883 का 19) या कृषि उद्यान अधिनियम, 1884 (1884 का 12) के अधीन उद्यान लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके प्रतिनिधियों द्वारा ऐसे अधिनियमों के चुनने के लिए प्रतिनिधित्व के रूप में निष्पादित की गई है।

17. अनुच्छेद-46—

18. अनुच्छेद-48 विभाजन—

19. अनुच्छेद-53 —

20. अनुच्छेद-56—
<table>
<thead>
<tr>
<th>अनुक्रम क्र.</th>
<th>अनुच्छेद</th>
<th>कमी / छूट</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
</tr>
<tr>
<td>नहीं है।</td>
<td>2. किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रतिपादिति देने के प्रयोजन के लिए किसी धार्मिक ऐश्वर्यवाद या अनुशासन या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गए प्राइवेट बन्दो से युक्तन स्थानीय आय प्रतिमाह विनिर्मित राशि से कम नहीं होगी, निषादित प्रतिपूर्ति वंशपत्र पर।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3. ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने गृहा विकास उपयोग अधिनियम, 1883 (1883 का 19) या कृषि उपयोग अधिनियम, 1884 (1884 का 12) के अधीन अधिम लिए है या उनके प्रतिनिधियों द्वारा ऐसे अधिम के चुना दिए जाने के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में निषादित प्रतिपूर्ति वंशपत्र पर।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4. सरकार के अधिकारियों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा किसी पद के कर्तव्यों के समयक नियोजन को या उनके अपने पद के आदेश पर प्राप्त धनसूची या अन्य सूचना का सम्पूर्ण रूप से लेख देने को सुनिश्चित करने के लिए निषादित प्रतिपूर्ति वंशपत्र पर।</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

21. अनुच्छेद 57- पद्धति का अन्तर्दर्शन—

विवाह के अवसर पर नवजागरण के बीच निषादित किया गया मेहर विलेख चाहे ऐसा विलेख विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात् निषादित किया गया हो।

22. अनुच्छेद 60- पद्धति का अन्तर्दर्शन—

पट्टे का अम्लित जबकि ऐसे पट्टे को शुल्क से छूट दी गई हो।

23. अनुच्छेद 61- अंतर्ण—

पुष्करण द्वारा अंतर्ण—

(क) जो विपनय-पद, वैयक्त या वचन-पत्र का है;

(ख) वचन-पत्र, परिदर्शन आदेश, जो के लिए प्रारंभ या माल पर हक की अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज का है;

(ग) बीमा पालिसी का है;

(घ) केंद्रीय सरकार की प्रतिपूर्तियों का है।

24. अनुच्छेद 62- पद्धति का अन्तर्ण—

शुल्क से छूट प्राप्त किसी पट्टे का अंतर्ण।

टिप्पणी:— इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. “बैंक” में सम्बदित है—

(क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) में यथा परिवर्तित कोई बैंककारी कंपनी;

(ख) भारतीय बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक;

(ग) भारतीय स्टेट बैंक (समग्र अधिनियम) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथा परिवर्तित समग्र अधिनियम बैंक;

(घ) बैंककारी कंपनी (उपकरण का अर्जन और अंतर्ण), अधिनियम, 1970 (1970 का 5) के अधीन गठित तत्कालीन नौवीं बैंक;

(ड) मध्यप्रदेश स्टेट एंड एपो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्यालय लिमिटेड, भोपाल।
2. “वित्तीय संस्था” में सम्मिलित हैं—

(क) मध्यप्रदेश वित्त निगम ;

(ख) मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम ;

(ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) में यथा परिस्मारित कोई बैंककारी कम्पनी ;

(घ) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक.

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक (समुदायी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 39) में यथा परिस्मारित समुदायी बैंक ;

(च) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) के अधीन गठित तर्कशायर कोई भारतीय बैंक ; और

(छ) कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन यथाविनिर्देशित कोई लोक वित्तीय संस्था।

3. “कृषिक प्रयोजन” से अभिवृद्धि है भूमि को खेती के योग्य बनाना, भूमि का सुधार करना जिसमें सममिलित है सिंचाई से स्रोतों का विकास, फसलों को उगाना तथा काटना, उद्यान कृषि, बनोढयोग लए चूना कर्म, पशु प्रजनन, पशु पालन, दुर्घटना बीमा कृषि, मक्ख पालन, भूमिकृती पालन, रसायन उत्पादन, सुअर पालन एवं खुद्धुत पालन और ऐसे क्रियालाप के संबंध में दूसरे, भिन्न दूसरे, मेटाइंडर तथा आविलिन मशीन व छोड़कर अन्य उपकरणों तथा मशीनों का अर्जन करना तथा उसका उपयोग।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी, 2015

क्र. एफ वी-4-29-2014-2-पांच,—भारत के संविधान के अनुसार 348 के खंड (3) के अनुसार में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ वी-4-29-2014-2-पांच (01), दिनांक 2 जनवरी, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रधानकार से एल्ट्टरार्स प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.
Bhopal, the 2nd January 2015

No. F. B-4-29-2014-2-V(01).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government, hereby, reduce/remit stamp duty on documents mentioned in column (3) of the table below on the articles mentioned in column (2) of Schedule 1-A of the said Act, namely :—

TABLE

<table>
<thead>
<tr>
<th>S.No.</th>
<th>Article (1)</th>
<th>Reductions / Remissions (3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Article - 5 - Affidavit</td>
<td>1. On affidavit affirmed by a member of a Scheduled Castes or Scheduled Tribes.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. On affidavit sworn or affirmed by a member of the Other Backward Classes, as specified in the State Government notification No. F-8-5-25-4-84, dated the 26th December, 1984, as amended from time to time.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. On affidavit submitted before a Commission of Inquiry appointed by the Government of India or the State Government under the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6. On affidavit made for the sole purpose of being filed or used in any Court or before the officer of any Court.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>7. On affidavit made for the sole purpose of enabling any person to receive any pension or charitable allowance.</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Article - 6 - Agreement or Memorandum of an agreement</td>
<td>1. On instruments executed by units under Madhya Pradesh Khadi and Gramodyog Board for obtaining assistance from the Board.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. On instruments of agreement required to be executed by eligible users belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes living below the poverty line with the Madhya Pradesh Vidyut Vitaran Company Jabalpur, Bhopal, and Indore for obtaining single-point metered electricity connection.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. On instruments executed by agriculturists in favour of Banks for securing loans under the Kisan Credit Card Scheme.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4. On instrument executed by Self Help Groups in favour of banks for securing loans upto Ten Lakh Rupees for economic development of group members under the NABARD sponsored schemes.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. **Article - 7 - Agreement relating to deposit of title deeds, pawn, pledge or hypothecation**

1. On instruments executed by units under Madhya Pradesh Khadi and Gramodyog Board for obtaining assistance from the Board.

2. On agreements relating to deposit of title deeds executed by industrialists or industrial undertakings in the State in connection with obtaining loans or advances for industrial purposes from Khadi and Village Industries Commission and Madhya Pradesh Khadi and Gramodyog Board.

3. On instruments executed by agriculturists in favour of Banks for securing loans under the Kisan Credit Card Scheme.

4. On instruments executed by Self Help Groups in favour of banks for securing loans for economic development of group members to the limit of 10 Lakh Rupees under the NABARD sponsored schemes.

5. Stamp duty is exempted on instruments executed by herbal or ayurved based industry in favour of any financial institution, to secure repayment of loans obtained for industrial purposes only till the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010, as amended in 2012 or the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work-plan remains in operation subject to the conditions, that:—

(a) the industrial unit is situated in an industrial area or industrial growth centre developed by the Government of Madhya Pradesh or Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam; and

(b) a certificate of eligibility to the effect that the industry is eligible for remission of stamp duty under this order, is issued by the Commissioner of Industry, Government of Madhya Pradesh.

6. On instruments of agreement related to development of Government land executed by the Tourism Department of the State for tourism projects.

7. Stamp duty is reduced to Rupees Five Hundred only on instruments of agreement relating to repayment of education loan.

8. Stamp duty is reduced to Rupees Five Hundred only on loan related instruments to be executed with Banks for establishment of technical educational institutions.

9. On Agreement or memorandum of an agreement—

(a) for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively, not being a Note or Memorandum chargeable under article 46.

(b) made in the form of tenders to the Central Government for or relating to any loan.
5. On instruments of hypothecation executed in favour of banks for securing loan upto Ten Lakh Rupees for agricultural purposes by any Bhumiwami or a pattadhar holding land under Revenue Book Circular -IV-3-10. Also, no stamp duty shall be chargeable for this purpose up to any limit in case of a person belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

6. On instruments executed by herbal or ayurved based industries in favour of any financial institution, to secure repayment of loans obtained for industrial purposes only till the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2010 as amended in 2012 or Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work plan remains in operation subject to the conditions, that :

(a) the industrial unit is situated in an industrial area or industrial growth centre developed by the Government of Madhya Pradesh or Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam ; and

(b) a certificate of eligibility to the effect that the industry is eligible for remission of stamp duty under this order, is issued by the Commissioner of Industry, Government of Madhya Pradesh.

7. On instruments of equitable mortgage/hypothecation executed by a new unit/expanded unit/ modernized unit of an Information Technology/ Business Process Outsourcing company for obtaining loans from banks/ financial institutions in Information Technology investment area, subject to the condition that the new unit/ expanded unit/ modernized unit is certified to be an information technology/ Business Process Outsourcing outfit by Information Technology Department or any designated agency notified by them under the Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012, as amended 2014 or Madhya Pradesh Business Process Outsourcing/ Business Process Management (Business Process Outsourcing /Business Process Management) Industry Investment Policy, 2014 of the State of Madhya Pradesh.

Note—This exemption shall be applicable only till the Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012, as amended in 2014 or Madhya Pradesh Business Process Outsourcing/ Business Process Management (BPO/BPM) Industry Investment Policy, 2014 remains in operations.

8. Stamp duty is reduced to 0.125 percent of the amount of loan secured on instruments of agreement relating to deposit of title deeds for securing loans upto rupees ten crore in case of micro and small scale industries and on loans for residential purposes.

9. On instruments relating to deposit of title deeds, executed by beneficiary in favour of any bank or financial institution for securing repayment of loan or advance upto Rs. One Lakh to be received by him for the purpose of construction of house under the Mukhyamantri Gramin Awas Yojna, subject to the condition that a certificate of eligibility to the effect that the beneficiary is eligible for the remission of stamp duty is issued by the Collector of the concerned district.
<table>
<thead>
<tr>
<th>4. Article - 9 - Appraisal or valuation</th>
<th>1. On Appraisal or valuation made for the information of one party only, and not being in any manner obligatory between parties either by agreement or operation of law.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2. On Appraisal of crops for the purpose of ascertaining the amount to be given to a landlord as rent.</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Article - 10 - Apprenticeship deed</td>
<td>1. On contracts executed by an adult apprentice or by the guardian of a minor apprentice in favour of an employer under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961).</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. On instruments of apprenticeship by which a person is apprenticed by or at the charge of any public charity.</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Article - 14 - Bond</td>
<td>On Bond when executed by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem.</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Article - 16 - Cancellation</td>
<td>On instrument of cancellation of a will.</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Article - 25 - Conveyance</td>
<td>1. On the instruments of sale executed by Madhya Pradesh Housing Board, Nagar Vikas Pradhikarans, Primary Co-operative Housing Societies and Madhya Pradesh State Co-operative Housing Federation, in relation to house/apartment to the extent of the value of the house/apartment (excluding value of plot) constructed under self financing scheme, with the money received from the purchaser, subject to following conditions, namely:—</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(a) the chargeable stamp duty shall be exempted/reduced to the extent of 100 percent, 50 percent and 25 percent for the categories of house/apartment of Economically Weaker Section, Low Income Group and Middle Income Group respectively, but no exemption/reduction shall be granted in cases of High Income Group houses/apartments;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(b) this exemption/reduction shall be limited only to original allottees under the Self Financing Scheme.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(c) economically Weaker Sections, Low Income Group and Middle Income Group shall be as defined and specified by the Department of Urban Development and Environment from time to time:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Provided that this remission shall not be available in case of partly constructed house/apartment.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. On all kinds of deeds of transfers of agricultural land executed by a person belonging to a Scheduled Tribes in favour of his legal heir/heirs during his life time.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. On instruments of sale relating to plot or built up space executed by or on behalf of State Government or any Semi Government Organization or any Government Undertaking, in favour of Information Technology/ Business Process Outsourcing Industries to be established in the State of Madhya Pradesh.

4. On instruments of conveyance of industrial units as a going concern, the rate of duty on the value of plant, machinery and other moveables conveyed by the instrument shall be one percent, and also the duty chargeable on a single instrument shall not exceed rupees ten crore.

5. On instruments of sale executed by or on behalf of financial institutions, Government Agencies, or Private Sector by which space/premises in an Information Technology investment area is transferred in favour of a new unit/ expanded unit/ modernized unit of an IT/ Business Process Outsourcing company, subject to the condition that it is certified to be an information technology/ Business Process Outsourcing outfit by Information Technology Department or any designated agency notified by them under the Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012, as amended in 2014 or the Madhya Pradesh Business Process Outsourcing/ Business Process Management (BPO/BPM) Industry Investment Policy, 2014 of the State of Madhya Pradesh.

Note — This exemption shall only be applicable till the Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012, as amended 2014 or Madhya Pradesh Business Process Outsourcing/ Business Process Management (BPO/BPM) Industry Investment Policy, 2014 remains in operations.

6. On instruments of sale of land executed in favour of persons, whose land has been acquired for Auto Testing Track Project, Pithampur, District Dhar, the chargeable stamp duty shall be remitted subject to the following conditions, namely :—

(a) a certificate in the enclosed format from the Collector of Dhar District is obtained , in which the amount of compensation as well as special rehabilitation grant paid for acquisition of land for Auto Testing Track Project , Pithampur is mentioned;

(b) the position in clause(a) above, is expressed in the instrument of sale itself; and

(c) the eligibility of exemption shall be limited to the amount of stamp duty chargeable on the amount of compensation and special rehabilitation grant.

(d) the stamp duty chargeable on such instrument in accordance with the provisions of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899) shall be reimbursed by the Commerce, Industry and Employment Department to the Commercial Taxes Department within one month from the date of registration of the instrument.
CERTIFICATE

No.................. Dated..................

Certified that land having area............. hectare of Shri.............R/o Village............Tehsil ..............District Dhar has been acquired for Auto Testing Track Project, Peethamgur, District Dhar, for which the amount of compensation and special rehabilitation grant paid is as under:

Compensation Amount
- 

Amount of Special Rehabilitation grant
- 

Total
- 

2. This certificate shall be applicable for granting exemption of stamp duty on deed of sale of land having area.............hectare situated at Village ..................................executed by Shri............. S/o Shri.........................in favour of Shri
.............S/o Shri.............. After this registry, the eligibility of exemption of stamp duty shall be available only to the extent of duty chargeable on Rs..................... the balance amount of compensation and special rehabilitation grant. But in no case the amount of duty exempted shall exceed the amount of duty chargeable on the sum of amount of compensation and special rehabilitation grant obtained by Shri............. S/o Shri..............

Collector,
Dhar

7. Stamp duty shall be reduced to half on instrument of sale executed by private persons in favour of a Unit established to generate electricity from non-conventional energy resources subject to the following conditions, namely:

(a) a Bank Guarantee of the sum equal to the amount of stamp duty remitted shall be given by the unit in favour of the State Government for a period of 21 months in case of Wind Energy or Solar Energy Projects and for a period of 36 months in case of Bio-gas or Municipal Waste projects; and

(b) the unit shall be liable to pay the amount of stamp duty remitted to the State Government, if the project is not established within the given period of Bank Guarantee. It shall also be the responsibility of the unit to produce before the District Registrar of the concerned district in which the land purchased is situated, a certificate from the Competent Authority appointed by the Energy Department in this behalf, that the unit has been established before the prescribed period of Bank Guarantee. In case of default, the amount of duty remitted shall be recoverable from the Bank Guarantee tendered by the unit for the purpose.

8. On instruments of transfer of developed land in a Food Park executed by the developer of the park in favour of a Food Processing Unit, the
remission shall be granted subject to the following conditions, namely:—

(a) the duty charged on the instrument of purchase of the said land shall be adjusted in proportion to the part of land transferred; and

(b) if on adjustment no duty is required to be paid, then the minimum duty for the transfer shall be rupees five Hundred only.


10. On instruments of sale executed by the Madhya Pradesh Housing Board, Nagar Vikas Pradhikarans, Madhya Pradesh State Co-operative Housing Federation or any Urban Local Body in Madhya Pradesh in favour of a person of economically weaker section.

“Economically Weaker Section” shall be as defined and specified by the Department of Urban Development and Environment from time to time. A certificate from the District Collector to this effect shall have to be produced.

The remission of stamp duty shall also be available where the instruments of lease of residential house is executed under the Basic Service For Urban Poor (B.S.U.P.)/Integrated Housing and Development Program (I.H.S.D.P.) in favour of a person, who surrenders the lease already held by him under the Madhya Pradesh Nagaraya Kshetra Ke Bhoomihiin Vyakti (Pattadhrity Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 from the Government on the sites under construction by the said agencies.

11. Instruments of conveyance relating to conversion of lease hold rights into freehold rights of private or nazul land executed by or on behalf of the Government or a Semi-Government Organization or any Government undertaking or Housing Co-operative Society established or registered under any law for the time being in force, shall be chargeable in reduction to the extent only on the amount of consideration paid for the conversion, as set-forth in the instrument, but in no case shall the amount of duty chargeable be less than rupees Five Hundred.

12. On the instrument of sale of sick/closed industrial units which are referred to the Board of Industrial Finance and Reconstruction (B.I.F.R.) or a liquidator or acquired by financial institutions or banks or which fall in the category of sick industry as defined by the Reserve Bank of India, subject to the conditions that,—

(i) the remission shall be granted only once. On conveyance of unit/assets on which exemption under this notification has been granted once, no exemption in any case shall be granted again;

(ii) the remission shall be granted only to such closed and sick units in which the high power committee headed by the Chief Secretary of the
State of Madhya Pradesh or the Empowered Committee headed by the Collector of the District, as the case may be, constituted under the provisions of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010, as amended 2012 or Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work plan has taken a decision to remit the stamp duty;

(iii) to obtain remission the purchaser of unit will have to produce a scheme for revival of the unit before the competent authority explaining his financial position. Also the purchaser shall give an undertaking before the Competent Authority that he will revive the industry within eighteen months and in case of violation pay the amount of stamp duty remitted along with an interest at the simple rate of 0.75 percent for every month or part thereof from the date of execution of the instrument. For revival he shall be entitled to use the option of diversification of the product; and

(iv) the remission shall be subject to the certificate of Competent Authority to the effect that the instrument is eligible for remission under this notification. The competent authority authorized to issue the said certificate shall be as under:—

<table>
<thead>
<tr>
<th>Value /Market value of the unit</th>
<th>Competent Authority</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(i) Where it does not exceed one crore rupees</td>
<td>Collector of the concerned District</td>
</tr>
<tr>
<td>(ii) Where it exceeds one crore rupees</td>
<td>Divisional Commissioner of the concerned Division</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Note—This exemption shall be applicable only till the operation of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010, as amended 2012 or Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work-plan.

13. On instruments of sale or merger or amalgamation of industrial units as a going concern stamp duty shall be reduced to a maximum of Ten Lakhs rupees when the amount chargeable exceeds that amount. This reduction in duty shall be applicable subject to the conditions that—

(a) the said instrument is executed for better capacity utilization of the industry,

(b) the production of the industry in any three of the immediately preceding five years has not exceeded 50 percent of the installed capacity,

(c) any bank or financial institution which has extended loan to the industry has considered its loan as non-performing asset for immediately preceding two years,

(d) the net worth of the industry has been reduced to less than one half of its net worth immediately preceding five years ago; and
(e) a certificate to the effect that the instrument is eligible for concession under this notification is issued by the Collector of the concerned District in cases where the sale price of the industry does not exceed rupees One Crore and by the Commissioner of the concerned division in other cases.

Note—The exemption under this notification shall be applicable only till the Madhya Pradesh Industrial Promotion policy 2010 as amended 2012 or Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work-plan remains in operation.

14. On instruments of conveyance of 12.713 acre land in the campus of former Higher Secondary Technical School, Shahdol and 8 hectare land of Government Survey No. 556/1 of Village Kalyanpura in Jhabua District in favour of Rajeev Gandhi Technical University, Bhopal for establishment of University Institute of Technology, a constituent institution of Rajeev Gandhi Technical University, Bhopal.

15. On instruments of conveyance of 12.120 hectare (25 acres) of total land of four survey numbers i.e. area 7.422 hectare out of 8.359 hectare of survey number 108/3, area 0.063 hectare of survey number 116, area 2.023 hectare of survey number 117/1, and area of 0.612 hectare out of 1.517 hectare of survey number 138, of Village Malsipur in Tehsil Sironj, executed in favour of Rajeev Gandhi Technology University, Bhopal for establishment of University Institute of Technology, Sironj, Vidisha District, a constituent institution of Rajeev Gandhi Technology University, Bhopal.

16. On instruments of purchase of land by displaced/ effected families, to the extent of payable compensation and special rehabilitation grant according to award in cases of land acquisition for establishing Thermal Power Project by M/s New Zone India Private Limited in District Anuppur, subject to the following conditions, namely:—

(a) the formal sanction shall be issued after the essential amount of expected compensation of stamp duty of rehabilitation package for this project is deposited in designated revenue head of public account by District Collector;

(b) a certificate in favour of every displaced family under rehabilitation package of this project shall be issued by the District Collector, in which the amount of compensation alongwith amount of special rehabilitation grant payable to displaced person shall be mentioned, and the entitlement of exemption of amount of stamp duty shall also be certified in it. This certificate shall be submitted by the displaced person at the time of registration of deed of acquired land before Registering Officer. The eligibility of exemption of payable stamp duty shall be limited to the extent of amount of compensation and special rehabilitation grant;

(c) the demand for reimbursement of stamp duty on the basis of registered deeds under this project shall be submitted every month by District Registrar to District Collector, and District Collector shall deposit the amount of reimbursement in account head “0030 Stamps and Registration” within one month from the date of receipt of demand; and
(d) the exemption on stamp duty shall be valid only for two years from the date of payment of compensation and rehabilitation grant.

17. On instruments of sale executed to acquire land in favour of member of a family displaced on account of the Narmada Valley Projects subject to the following conditions, namely:—

(a) a certificate from the Land Acquisition Officer of the project area is obtained in which the total amount including the amount of compensation item wise of his land and other immovable properties, special rehabilitation grant, rehabilitation grant etc., is mentioned. But the amount of transport fee paid for self transportation of goods shall not be included;

(b) the agricultural land and/or other immovable property is purchased by the displaced person anywhere in the State of Madhya Pradesh during the process of rehabilitation;

(c) the position in clause (a) and (b) above is expressed in the instrument of transfer itself;

(d) the eligibility of exemption shall be limited to the amount of Stamp duty chargeable on the value of land and/or immovable property or the total amount of consideration paid to the said displaced person as compensation, special rehabilitation grant, rehabilitation grant, financial assistance etc., whichever is less;

(e) the Stamp duty chargeable on the instrument will be reimbursed by the Narmada Valley Development Authority to Commercial Tax Department on the basis of demand letter produced by the Sub-Registrar;

(f) only a displaced family as defined in the Rehabilitation Policy shall be entitled for exemption; and

(g) such landless displaced person and adult son, who want to purchase agricultural land and/or other immovable property from various amounts such as rehabilitation grant, financial assistance given to purchase productive assets, financial assistance given for developed residential plot at the rehabilitation place, shall also be entitled for the said exemption.

18. On instruments executed for,—

(a) transfer of land acquired by the Commerce, Industry and Employment Department of the State Government, to the Special Purpose Vehicle (SPV) Company constituted for establishment of Vikram Udyogpuri Project in District Ujjain under Delhi-Mumbai Industrial Corridor sub-region in the State of Madhya Pradesh;

(b) for first transfer of a parcel of land by Special Purpose Vehicle to any developer, tenderer, construction company or joint venture in the course of execution of the Master Plan of the above mentioned Vikram Udyogpuri Project. It is clarified that for this purpose, certificate from Managing Director, TRIFAC or any other officer authorised in this behalf shall be required.

1. On copy of any paper which a public officer is expressly required by law to make or furnish for record in any public office or for any public purpose.

2. On copy of extract from any register relating to births, baptisms, namings, dedications, marriages, divorces, deaths and burials.

On counterpart of any lease granted to a cultivator when such a lease is exempted from duty.

11. Article - 34 - Exchange of Property.

Stamp duty chargeable on deeds of exchange of agricultural land upto two hectare is remitted under following conditions, namely:—

(a) the lands being exchanged are agricultural;
(b) the lands being exchanged are approximately of equal market value;
(c) the lands being exchanged shall not be Nazul or extra-Nazul agricultural lands;
(d) the lands being exchanged are situated within the same Revenue Inspector Circle; and
(e) provision shall not be misused for evading Ceiling on agricultural land.

12. Article - 35 - Further charge

1. On instruments of further charge without possession executed in favour of banks for securing loan up to ten lakh rupees for agricultural purposes by any Bhumi Swami or a pattadari holding land under Revenue Book Circular -IV-3-10. Also, no stamp duty shall be chargeable for this purpose up to any limit in case of a person belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

2. On instruments executed by agriculturists in favour of Banks for securing loans under the Kisan Credit Card Scheme.

13. Article - 36 - Gift

1. On instrument of gift executed in favour of the State Government.

2. On instruments of gift of land executed in favour of a Goshala registered by the Madhya Pradesh Gopalan Evam Pashudhan Samwardhan Board, Bhopal.

3. On instruments of gift of Agricultural land executed by a person belonging to Scheduled Tribe in favour of his legal heir/heiress during his life time.

14. Article - 37 - Indemnity Bond

On indemnity bonds to be executed by the guardians of minor dependents of deceased members of the Coal Mines Provident Fund for the purpose of obtaining refund of the fund accumulations.

15. Article - 38 - Lease

1. On lease deeds executed in relation to the constructed sheds and land allotted to unemployed engineers in notified industrial area by the Commerce, Industries and Employment Department for running their own industry stamp duty shall be remitted subject to the following
<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>conditions, namely:—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(a) the applicant or all the partners of the firm are either degree or diploma-holder engineer;

(b) his total income or the income of his partners from all sources shall not exceed One Thousand rupees per month.

2. On instruments of lease executed by Government in favour of Madhya Pradesh State Tourism Corporation in relation to the land on which the units of the said corporation are situated.

3. On instruments of lease of the Government land executed by the Tourism Department of State of Madhya Pradesh for tourism projects.

4. On instruments of Lease relating to plot or built up space executed by or on behalf of State Government or any Semi Government Organization or any Government Undertaking, in favour of the Information Technology Industries to be established in the State of Madhya Pradesh.

5. On lease deed executed in favour of a Fisherman Co-operative Society registered or deemed to be registered under the Madhya Pradesh Co-operative societies Act, 1960(No. 17 of 1961) relating to catch fishes from a reservoir and measuring not more than two thousand hectares in area.

6. On instruments of lease executed by a Gram Panchayat in favour of fishermen to catch fishes from the reservoir.

7. On instrument of lease executed by or on behalf of Financial Institutions, Government Agencies, or Private Sector by which space/premises in an Information Technology investment area is transferred in favour of a new unit / expanded unit/ modernized unit of an Information Technology/ Business Process Outsourcing company and is certified to be an Information Technology/ Business Process Outsourcing outfit by Information Technology Department or any designated agency notified by them under the Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012 as amended in 2014 or the Madhya Pradesh Business Process outsourcing/ Business Process Management (Business Process Outsourcing /Business Process Management) Industry Investment Policy, 2014 of the State of Madhya Pradesh.

**Note**—This exemption shall be applicable only till the operation of the Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012, as amended in 2014 or the Madhya Pradesh Business Process outsourcing/ Business Process Management (Business Process Outsourcing /Business Process Management) Industry Investment Policy, 2014 remains.

8. On instruments of amendment of lease executed by the Commerce, Industries and Employment Department of Madhya Pradesh or Madhya Pradesh Ayudhyak Kendra Vikas Nigam in favour of herbal or ayurved based industry due to change of name of the industry, addition of a
partner/ partners, collaboration or its reconstruction, subject to the following conditions, namely:

(a) the industrial unit is situated in an industrial area or industrial growth centre developed by the Government of Madhya Pradesh or Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam; and

(b) a certificate of eligibility to the effect that the industry is eligible for remission of stamp duty is issued by the Commissioner of Commerce, Industries and Employment Department, Government of Madhya Pradesh.

Note—This exemption shall be applicable only till the operation of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010, as amended in 2012 or the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work-plan remains.

9. On instruments of lease executed by the Madhya Pradesh Housing Board, Nagar Vikas Pradhanikarans, Madhya Pradesh State Co-operative Housing Federation or any urban Local Body in Madhya Pradesh in favour of a person of Economically Weaker Section as defined and specified by the Urban Development and Environment Department from time to time. A certificate from the District Collector to this effect shall have to be produced.

The remission of stamp duty shall also be available where the instrument of lease of residential house is executed under the Basic Service For Urban Poor (B.S.U.P.)/Integrated Housing and Development Program(I.H.S.D.P.) in favour of a person, who surrenders the lease already held by him under the Madhya Pradesh Nagariya Kshetro Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984) from the Government on the sites under construction by the said agencies.

10. On instrument of amendment of lease of land and sheds in the Industrial Areas and Industrial Growth Centers, executed by or on behalf of the State Government or any undertaking of the State Government, chargeable in reduction to the extent of only the amount of transfer fees set-forth in the instrument treating it as the amount of market value for the lease:

Provided that in each case certificate shall be produced by the parties from the Collector of Stamps of the concerned District, where the land is situated, to the effect that the proper duty has been paid on the instruments on the basis of which the amendment in the lease was permitted by the Government or the concerned undertaking of the Government.

Note.—This exemption shall be applicable only till the operation of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2010 as amended in 2012 or the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work-plan remains.
11. On instrument of lease of sick/closed industrial units which are referred to the Board of Industrial Finance and Reconstruction (B.I.F.R.) or a liquidator or acquired by financial institutions or banks or which fall in the category of sick industry as defined by the Reserve Bank of India, subject to the conditions, that –

(a) the remission shall be granted only once. The unit/assets on which exemption has been granted once, no exemption in any case shall be granted again;

(b) the remission shall be granted only to such closed and sick units in which the high power committee headed by the Chief Secretary of the State of Madhya Pradesh or the Empowered Committee headed by the Collector of the District, as the case may be, constituted under the provisions of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010, as amended in 2012 or the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work plan has taken a decision to remit the stamp duty.

(c) to obtain remission, the lessee of the unit shall have to produce a scheme for revival of the unit before the Competent Authority explaining his financial position. Also the lessee shall give an undertaking before the Competent Authority that he shall revive the industry within eighteen months and in case of violation, he shall pay the amount of stamp duty remitted along with an interest at the simple rate of 0.75 percent for every month or part thereof from the date of execution of the instrument. For revival he shall be entitled to use the option of diversification of the product; and

(d) the remission shall be subject to the certificate of Competent Authority to the effect that the instrument is eligible for remission under this notification. The Competent Authority authorized to issue the said certificate in the following manner, namely :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Value /Market value of the unit</th>
<th>Competent Authority</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(i) Where it does not exceed</td>
<td>Collector of the concerned District</td>
</tr>
<tr>
<td>Rupees One Crore</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ii) Where it exceeds Rupees</td>
<td>Divisional Commissioner of the</td>
</tr>
<tr>
<td>One Crore</td>
<td>concerned Division.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Note.—This exemption shall be applicable only till the operation of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010, as amended in 2012 or the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work plan.

12. On instruments of lease executed to acquire land in favour of member of a family displaced on account of the Narmada Valley Projects subject to the following conditions, namely :

(a) a certificate from the land acquisition officer of the project area is obtained in which the total amount including the amount of compensation item wise of his land and other immovable properties, special rehabilitation grant, rehabilitation grant etc., is mentioned. But the amount of transport fee paid for self transportation of goods shall not be included;
(b) the Agricultural land and/or other immovable property is purchased by the displaced person anywhere in the State of Madhya Pradesh during the process of rehabilitation;

(c) the position in clause (a) and (b) above is expressed in the instrument of transfer itself;

(d) the eligibility of exemption shall be limited to the amount of Stamp duty chargeable on the value of land and/or immovable property or the total amount of consideration paid to the said displaced person as compensation, special rehabilitation grant, rehabilitation grant, financial assistance etc., whichever is less;

(e) the stamp duty chargeable on the instrument will be reimbursed by the Narmada Valley Development Authority to the Commercial Tax Department on the basis of demand letter produced by the Sub-Registrar;

(f) only a displaced family as defined in the Rehabilitation Policy shall be entitled for exemption; and

(g) such landless displaced person and adult son, who want to purchase agricultural land and/or other immovable property from various amounts as Rehabilitation grant, financial assistance given to purchase productive assets, financial assistance given for developed residential plot at the rehabilitation place, shall also be entitled for the said exemption.

13. On lease executed in case of a cultivator and for the purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink) without the payment or delivery of any fine or premium, when a definite term is expressed and such term does not exceed one year or when the average annual rent reserved does not exceed one hundred rupees.

14. Stamp duty chargeable under this article is reduced to rupees one thousand on agreements executed by a State Government Undertaking giving right to collect tolls on construction of road, bridge etc. under the Build, Operate and Transfer (B.O.T.) Scheme.

16 **Article - 43** - Mortgage deed

1. On instrument of conveyance of mortgaged property executed by the Madhya Pradesh Housing Board established under the Madhya Pradesh Housing Board Act, 1960 in favour of any officer of the Government of Madhya Pradesh on the repayment of an advance received by him from the said Board for the purpose of constructing a dwelling house for his own residential use.

2. On instruments of mortgage executed by unemployed engineers to secure loans upto One Lakh Rupees from Madhya Pradesh Finance Corporation by the Commerce, Industries and Employment Department for running their own industry on the following conditions, namely:—

   (a) The applicant or all the partners of the firm are either degree or diploma-holder engineers, and
(b) His total income or the income of all partners or income of his/her parents does not exceed One Thousand rupees per month.

3. On instruments of mortgage without possession executed by small scale Industrial units for obtaining financial assistance up to Rs. 7.5 lakhs from the Madhya Pradesh Finance Corporation.

4. On instruments of mortgage without possession executed by a “New Industry” to be set up in the field of energy generation and mineral oil refining, for raising capital to set up the industry, to Five Lakhs rupees where the duty payable on such deed exceeds that amount.

Explanation—For this purpose “New Industry” means an industrial unit which has not gone into production before 19.08.1999 and is so certified by the Commissioner of Commerce, Industries and Employment or any officer appointed by him in this behalf.

5. On instruments of mortgage without possession executed by industrialists or industrial undertakings in the State in connection with obtaining loans or advances for industrial purposes from the Khadi and Village Industries Commission and Madhya Pradesh Khadi and Gramodyog Board.

6. On instruments of mortgage without possession executed by industrialists or Industrial Undertaking in the State of Madhya Pradesh in connection with obtaining term loan, for the purpose of setting up a new industry, or for the expansion, diversification or modernisation of a industry from the Banks/Financial Institutions to the extent as specified in the table given below:—

<table>
<thead>
<tr>
<th>Class of the District/Blocks (as per classification by the Commerce, Industries and Employment Department, Government of Madhya Pradesh)</th>
<th>Extent of remission/reduction of Stamp Duty For Small Scale Industry</th>
<th>Extent of remission/reduction of Stamp Duty For Medium and Large Industry</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Backward “B”</td>
<td>100%</td>
<td>50%</td>
</tr>
<tr>
<td>Backward “C”</td>
<td>100%</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td>Blocks which have no industry</td>
<td>100%</td>
<td>100%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

The aforesaid remission or reduction shall be subject to the conditions, namely:—

(a) The remission in case of small scale industry shall be given only in those cases where the amount of capital investment on plant and machinery exclusively is more than rupees Five Lakh and it shall not come in category of service or trade;
(b) the entire loan amount shall be spent for the development of the industry in the State of Madhya Pradesh; and

(c) a certificate of eligibility to the effect that the industry obtaining the loan is eligible for the remission or reduction of stamp duty, is to be issued by the Commissioner Commerce, Industries and Employment, Madhya Pradesh.


Note.—This exemption shall be applicable only till the operation of the Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012 as amended 2014 or Madhya Pradesh Business Process outsourcing/ Business Process Management (BPO/BPM) Industry Investment Policy, 2014.

8. On instruments of mortgage without possession executed by agriculturists in favour of Banks for securing loans under the Kisan Credit Card Scheme.

9. On instruments of mortgage without possession executed by Self Help Groups in favour of Banks for securing loans for economic development of group members to the limit of rupees Ten Lakh under the NABARD sponsored schemes.

10. No stamp duty shall be chargeable on instruments of mortgage without possession executed in favour of Banks for securing loan up to rupees Ten Lakh for agricultural purposes by any Bhumiswami or a pattadhari holding land under Revenue Book Circular -IV-3-10. Also, no stamp duty shall be chargeable for this purpose upto any limit in case of a person belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

11. On instruments executed by herbal or ayurved based industry in favour or any financial institution to secure repayment of loans obtained for industrial purposes. remission shall be subject to the conditions, namely :—

(a) the industrial unit is situated in an industrial area or industrial growth centre developed by the Government of Madhya Pradesh or the Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam ; and

(b) a certificate of eligibility to the effect that the industry is eligible for remission of stamp duty under this order, is issued by the Commissioner of Commerce, Industries and Employment, Madhya Pradesh.
Note.—This exemption shall be applicable only till the operation of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2010 as amended in 2012 or the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work plan remains.

12. On instruments of simple mortgage executed by beneficiary in favour of any bank or financial institution for securing the repayment of loan or advance upto rupees One Lakh to be received by him for the purpose of construction of house under the Mukhyamantri Gramin Awas Yojna, subject to the condition that a certificate of eligibility to the effect that the beneficiary is eligible for the remission of stamp duty is issued by the Collector of the concerned district.

13. On instruments of mortgage without possession executed to obtain loans from Banks and Financial Institutions for setting up a new Food Processing Industry, that uses perishables items included in Annexure-3 of the Madhya Pradesh Food Processing Policy, 2008 as raw material or for the expansion, diversification or modernization of such industry in the State of Madhya Pradesh.

14. Instrument executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883 (19 of 1883) or the Agriculturist’s Loans Act, 1884 (12 of 1884) or by their sureties as security for the repayment of such advances.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article - 46 - Note or Memorandum</th>
</tr>
</thead>
</table>
| On Note or Memorandum send by a broker or agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal or a Government Security or a share, scrips, stock, bond, debenture, debenture-stock or other marketable security of like nature in or of any incorporated company or other body corporate, an entry relating to which is required to be made in clearance lists described in clauses (a) and (b) of article 22.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article - 48 - Partition</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1. On deeds of partition of agricultural land between joint khatedars the chargeable stamp duty shall be remitted under following conditions, namely :—  
(a) There is neither any dispute nor any case pending in any court regarding the land to be partitioned; and  
(b) The land being partitioned is not within the provisions of ceiling.  
2. On such instrument of partition by which exclusively the agricultural land obtained in inheritance is partitioned amongst the members of joint family. |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Article - 53 - Re-conveyance of Mortgaged Property</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>On instrument of reconveyance of mortgaged property executed by the Madhya Pradesh Housing Board established under the Madhya Pradesh Housing Board Act, 1960 in favour of any officer of the Government of Madhya Pradesh on the repayment of an advance received by him from the said Board for the purpose of constructing a dwelling house for his own residential use.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
20 Article - 56 - Security bond not being a Mortgage deed

1. On security bond executed by the surety of an officer of the Government of Madhya Pradesh for the due performance of the terms and conditions of the mortgage deed in Form V presented under the Madhya Pradesh Housing Board Act, 1960.

2. On security bond executed by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem.

3. On security bond executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883 (19 of 1883) or the Agriculturist’s Loans Act, 1884 (12 of 1884) or by their sureties as security for the repayment of such advances.

4. On security bond executed by officers of the Government or their sureties to secure the due execution of an office or the due accounting for money or other property received by virtue thereof.

21 Article - 57 - Settlement

On instrument of dowry executed on the occasion of marriage between Mohammedans, whether the deed was executed before or after the marriage.

22 Article - 60 - Surrender of lease.

On surrender of lease, when such lease is exempted from duty.

23 Article - 61 - Transfer

On transfers by endorsement—

(a) of a bill of exchange, cheque or promissory note;

(b) of a bill of landing, delivery order, warrant for goods, or other mercantile documents of title to goods;

(c) of a policy of insurance; and

(d) of securities of the Central Government.

24 Article - 62 - Transfer of lease

On transfer of any lease exempt from duty.

Note:—For the purpose of this notification—

1. the “Bank” includes—

(a) a Banking Company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(b) the State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955);

(c) a Subsidiary Bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959);

(d) a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 (5 of 1970);

(e) the Madhya Pradesh State Agro Industries Development Corporation Limited, Bhopal;

(f) Agricultural Finance Corporation Limited, a company incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
(g) a Regional Rural Bank established under sub-section (1) of Section 3 of Regional Rural Bank Act, 1976 (21 of 1976);

(h) a Central Development Bank within the meaning of clause (b) of Section 2 of the Madhya Pradesh Sahakari Bhoomi Vikas Bank Adhiniyam, 1966 (28 of 1966) or a Development Bank within the meaning of clause (d) of Section 2 of the said Act; and

(i) the Agricultural Refinance Corporation constituted under the Agricultural Corporation Act, 1963 (10 of 1963).

2. “Financial institution” includes -

(a) Madhya Pradesh Finance Corporation;

(b) Madhya Pradesh Audyogic Vikas Nigam;

(c) a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949(10 of 1949);

(d) State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955);

(e) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959);

(f) a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970); and

(g) a public financial institution as specified in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

3. “Agriculture purpose” means making land fit for cultivation of land, improvement of land including development of sources of irrigation, raising and harvesting of crops, horticulture, forestry, planting and farming, cattle breeding, animal husbandry, dairy farming, seed farming, pisciculture, apiculture, sericulture, piggery and poultry farming and the acquisition and implementation of machinery in connection with any such activity except Truck, Mini Truck, Matador and Drilling Machine.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secretary.